महिला सशक्तिकरण में वित्तीय समावेशन की भूमिका

*मनीषा नेगी

शोध सारांश

राष्ट्र की प्रगति एवं विकास हेतु समावेशी विकास अपरिहार्य है। विकास की मुख्यधारा में जब तक देश की आधी आबादी सम्मिलित नहीं होगी, तब तक सम्पूर्ण अर्थों में राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं हैं। परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में, लैंगिक समानता, समावेशी विकास एवं महिला सशक्तिकरण हेतु वित्तीय समावेशन पूर्वापेक्षा बन गया है। वित्तीय समावेशन की विभिन्न योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होते हैं। इन सुधारों की निरन्तरता बनाए रखने हेतु शोधार्थी द्वारा संबंधित सुझाव भी दिये गये हैं।

मुख्य बिंदुः समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, समानता, गुणात्मक सुधार

1. प्रस्तावना

भारत लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राष्ट्र है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य समावेशी विकास है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है, जो विकास की सामान्य प्रक्रिया में देश के समस्त नागरिकों को प्राप्त समान अवसर एवं समान लाभ पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप समतामूलक समाज की स्थापना संभव है। सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन समावेशी विकास के प्रमुख घटक है। समावेशी विकास ''सबका साथ, सबका विकास'' पर आधारित है। अतः समावेशी विकास के साकारीकरण हेतु विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु महिलाओं का समावेशन अपरिहार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन के गुणक प्रभाव है, जिनमें अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, निर्धनता निवारण एवं वेतन–असंगति कम करना आदि सम्मिलित है। महिलाओं का वित्तीय समावेशन विशेषतः लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है।[1] महिलाएं अपने वित्तीय आवश्यकताओं को समझ कर, वित्तीय स्त्रोतों पर उचित नियंत्रण करके स्वयं एवं परिवार के लिए सहायक होती है। अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्रों के शोषण से बच कर निर्धनता चक्र में फँसने के संकट को कम करती है, इसके अतिरिक्त समावेशन के माध्यम से महिलाएँ उत्पादक–आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होती है, जिसका मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः वित्तीय समावेशन महिला सशक्तिकरण के प्रमुखमाध्यमों में से प्रमुख एक है।

परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास की प्राप्ति हेतु महिलाओं का वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है। सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टेंड़ अप इंड़िया एवं भामशाह योजना (राजस्थान में संचालित) आदि वित्तीय समावेशन की महिला केन्द्रित योजनाएँ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। धर्मराजन कृष्णा ने अपने अध्ययन में पाया है, कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से स्व उद्यमिता हेतु औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्ति सरल रूप में संभव है, साथ ही महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, निर्भरता प्राप्त होती है।[2] राबिया स्पर्जन ने अपने अध्ययन में पाया है कि वित्तीय समावेशित महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु वित्तीय साक्षरता भी अति आवश्यक है, वित्तीय साक्षरता के अभाव में महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार संभव नहीं है।[3] धवन, नेहा के लेख में प्रधानमंत्री जन–धन योजना के पश्चात् महिलाओं के

समावेशन में मात्रात्मक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए, उनके औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्ति में जटिलता को भी बताया गया है।'' कॉमनवेल्थ डिस्कशन पेपर में लैंगिक समानता हेतु महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की महत्ता को समझाया गया है।[5]

2. अध्ययन की आवश्यकता

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1,2,10,193,422 है, जिसमें महिला जनसंख्या 586469174 है, जो कुल आबादी का 48 प्रतिशत है, परन्तु श्रम बल में महिला सहभागिता मात्र 25.6 प्रतिशत थी, जो पुरूषों के 53.3 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है।[6]

महिलाओं की सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है, अतः शोध के माध्यम से महिला सशक्तिकरण (सामाजिक–आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, संसाधनों पर नियंत्रण, स्व–निर्णयन एवं गत्यात्मकता/गतिशीलता आदि) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन की भूमिका का अध्ययन करना है।

3. शोध के उद्देश्य

वित्तीय समावेशित होने के पश्चात् महिलाओं के जीवन में आए विभिन्न सकारात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता का अध्ययन करना व सुझाव देना।

4. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध हेतु प्राथमिक समंकों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए राजस्थान के अजमेर जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा की 200 महिला खाताधारकों को चयनित किया गया है, जो विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध है। इनका चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

4.1 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन योजनाओं के परिणामस्वरूप महिला खाताधारकों में वृद्धि :

वर्ष 2014 के पश्चात्, वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना, वित्तीय समावेशन की महत्वकांक्षी योजना है, जिसके व्यापक प्रचार–प्रसार से वित्तीय अपवर्जित वर्ग विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में वित्तीय समावेशन के प्राथमिक कदम (औपचारिक, वित्तीय संस्थानों में खाते खुलवाना) की ओर उत्सहजनक प्रतिक्रिया परिलक्षित हुई।

तालिका

वर्ष, जब से बैंक में खाताधारक है

वर्ष	बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारक	
	आवृति	प्रतिशत
वर्ष 2011 से पूर्व	50	25%
वर्ष 2011–12 में	15	7.5%
वर्ष 2012–13 में	10	5%
वर्ष 2014 में वित्तीय समावेशन के राष्ट्रव्यापी अभियान के पश्चात्	125	62.5%
कुल	200	100%

आँकड़ों के अवलोकन से विदित होता है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा के महिला खाताधारकों में से 25 प्रतिशत 2011 से पूर्व ही वित्तीय समावेशित थे, 7.5 प्रतिशत खाताधारकों ने वर्ष 2011–12 में, 5 प्रतिशत खाताधारकों ने वर्ष 2012–13 में खाते खुलवाए। वर्ष 2014 में, वित्तीय समावेशन के राष्ट्रव्यापी अभियान (प्रधानमंत्री जन–धन योजना) के पश्चात् अधिकांश 62.5 प्रतिशत महिला खाताधारकों ने बैंक में खाते खुलवाए।

4.2 वित्तीय समावेशन के पश्चात् औपचारिक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्ति :

वित्तीय समावेशन से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाएँ अपनी पारिवारिक समस्या अथवा आपातकालीन संकट के समय ऋण हेतु अनौपचारिक वित्तीय संस्थान अथवा मित्र–रिश्तेदारों पर निर्भर रहती थी, जिससे ऋण–चक्रवृद्धि ब्याज के दुष्चक्र में फंस जाती थी, एवं शोषण का शिकार होती थी। परन्तु बैंक खातों से सम्बद्धता एवं स्वयं सहायता समूहों की सदस्या होने के बाद अब उनके वित्तीय आवश्यकताओं हेतु बैंकों पर निर्भरता बढ़ी है। औपचारिक वित्त संस्थान विश्वसनीय माध्यम है, इसके अतिरिक्त बैंकों से ऋण प्राप्ति तुलनात्मक रूप में सरल रूप में है।

तालिका
महिला खाताधारकों के ऋण के स्त्रोत

ऋण–स्त्रोत	बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारक	
	आवृति	प्रतिशत
मित्र एवं रिश्तेदार	10	5
बैंक	75	37.5
स्वयं सहायता समूह	105	52.5
सूक्ष्म वित्त संस्थान	12	6
सूदखोर	8	4
कुल	200	100%

क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ो के आधार पर, बैंक ऑफ बड़ौदा के 52.5 प्रतिशत खाताधारकों ने स्वयं सहायता समूह को 37.5 प्रतिशत खाताधारकों ने बैंक, 6 प्रतिशत खाताधारकों ने सूक्ष्म वित्त संस्थान, 5 प्रतिशत खाताधारकों ने मित्र एवं रिश्तेदार एवं 4 प्रतिशत खाताधारकों ने सूदखोरों को ऋण प्राप्त करने के प्रमुख स्त्रोत बताए हैं।

4.3 वित्तीय समावेशन की महिला सशक्तिकरण में भूमिका

सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान एवं स्व–उद्यम हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती है, परन्तु पूर्व में वित्तीय अपवर्जित होने के कारण जरूरतमंद तक समय पर सहायता नहीं पहुँचती थी एवं मध्यस्थों द्वारा सहायता राशि का गबन कर लिया जाता था। महिलाएं स्व उद्यमिता के बारे में अनभिज्ञ थी। परन्तु वर्ष 2014 के पश्चात्, प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप अब महिलाएँ वित्तीय समावेशित है, विभिन्न योजनाओं में परिवार की वयस्क महिला सदस्यता को मुखिया बनाया गया है, जिससे सहायता धनराशि प्रत्यक्षतः उनके खातों में आती है एवं वित्त पर उनका नियंत्रण बढ़ गया है। इसके अतिरिक्ति, वे महिलाएँ जो कुटीर उद्योग अथवा अपना व्यवसाय (सिलाई सेन्टर, डेयरी प्रबंधन, ब्यूटीपार्लर, टोकरी उद्योग एवं पारम्परिक हस्तकला उत्पाद से सम्बद्ध) प्रारम्भ करना चाहती हैं, परन्तु ऋण के अभाव में प्रारम्भ नहीं कर पाती थी, अब वित्तीय समावेशन के पश्चात् वे भी औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

आर्थिक आयाम, जीवन के प्रत्येक आयाम – मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक आयाम को प्रभावित करता है। अतः आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति संभव है, जिसमें वित्तीय समावेशन प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है।

तालिका
वित्तीय समावेशन के पश्चात् जीवन में परिवर्तन

समावेशन से जीवन में परिवर्तन	बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारक	
	आवृति	प्रतिशत
अपनी बात/विचार स्पष्ट रूप से कह सकते हैं	35	17.5%
पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी/संतान की शिक्षा, विवाह आदि।	45	22.5%
आर्थिक आत्म निर्भरता	90	45%
सामाजिक निर्णयों में भागीदारी	10	5%
व्यवसाय/आजीविका के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं	20	10%
कुल	**200**	**100%**

आँकड़ो के अध्ययन से स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन के पश्चात् जीवन में विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 45 प्रतिशत खाताधारकों के अनुसार आर्थिक आत्मनिर्भर हुए, 22.5 प्रतिशत के मतानुसार पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी, 17.5 प्रतिशत के मत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, 10.5 प्रतिशत के मतानुसार सामाजिक गत्यात्मक (आजीविका/रोजगार मेले/उत्पाद प्रदर्शनी हेतु स्वतंत्र रूप से यात्रा) बढ़ी एवं 5 प्रतिशत के अनुसार सामाजिक निर्णयों में सहभागिता में अभिवृद्धि हुई।

निष्कर्ष

विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु महिलाओं का वित्तीय समावेशन अपरिहार्य है। परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि समावेशन के व्यापक अर्थों को संदर्भगत कर, महिलाओं को वित्तीय समावेशित एवं वित्तीय जागरूक किया जाए। समावेशन के माध्यम से ही सशक्तिकरण संभव है, इस हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ अत्युत्तम प्रयास है। प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रशासनिक क्रियान्वयन के माध्यम से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है।

सुझाव

यद्यपि महिला सशक्तिकरण में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है, परन्तु शोध के समय शोधार्थी को यह सामान्य समस्या दृष्टिगत हुई कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध है, वे ही अधिक वित्तीय जागरूक एवं उनके बैंक खाते सक्रिय है, अन्य महिला खाताधारकों में वित्तीय जागरूकता एवं सक्रियता की कमी है। अतः शोधार्थी द्वारा उचित समाधान दिये गये हैं, जो निम्नलिखित है :

- बैंकों द्वारा शाखा स्तर पर वित्तीय साक्षरता अभियान संचालित किए जाने चाहिए ताकि महिलाएँ वित्तीय साक्षर, जागरूक बनें

- बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रतिनिधि (व्यवसायिक संवाददाता) के रूप में स्थानीय महिलाओं की नियुक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि महिलाएं सहजता से वित्तीय योजनाओं को समझ सकें।
- सरकार को महिलाओं के वित्तीय समावेशन में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को सहायक बनाना चाहिए एवं उद्यमिता हेतु सरल रूप में ऋण सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिए ऋण का पर्यवेक्षण स्थानीय निकायों (ग्राम सभाओं) द्वारा किए जाने चाहिए ताकि ऋण का दुरूपयोग नहीं हो एवं महिलाएँ सक्रिय रूप से उद्यम संचालन कर सकें।
- महिलाओं की आवश्यकताओं को सन्दर्भगत कर वित्तीय नीतियां बनानी चाहिए ताकि वित्तीय समावेशन के आयाम (पहुँच, उपयोग एवं गुणवत्ता की प्राप्ति संभव हो।

***शोधार्थी**
लोक प्रशासन विभाग
समाज विज्ञान संकाय,
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (राज.)

संदर्भ

1. Reserve Bank of India. (2020) National Strategy for Financial Inclusion 2019-24, Mumbai, page No. 1-2
2. Dharmrajan, Krishna. (2018) Financial Inclusion, the Key to Women's Empowerment in India, Page No. 3-4
3. Spurgeon, Rabia. (Oct-December 2019) Financial Inclusion, Financial Literacy and the Indian Woman, The Journal of Indian Institute of Banking and Finance, Page No. 15-17
4. Finnegan, Gerry. (2015) Strategies for Women's Financial Inclusion in the Commonwealth, Discussion paper, Page No. 30-35
5. Govt. of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation (2019) Women and Men in India, 2018, New Delhi, page No. i
6. Dhawan, Neha. (2020) Women Want to do more, but access to Credit is still Missing. Economic Times
7. https://pmjdy.gov.in
8. https://www.startupindia.gov.in
9. https://www.mudra.org.in